लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

# हरियाणा संवाद

पाक्षिक 16-30 अप्रैल 2021 www.haryanasamvad.gov.in अंक-16

"भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे है।"
: महात्मा गांधी

मॉडल संस्कृति स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम 3

मछलीपालन बना रोज़गार 5

जनमानस को राह दिखाता लोक साहित्य 8

# खरी फसल खरे दाम
## खरीद के हुए खास इंतज़ाम

विशेष प्रतिनिधि

अनाजमंडी व अन्य खरीद केंद्रों पर गेहूं की आवक व खरीद तेजी पकड़ चुकी है। प्रदेश में इस बार गेहूं का रिकार्ड 125 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान है। हालांकि खरीद केंद्रों पर 80 लाख टन गेहूं आने की उम्मीद है लेकिन राज्य सरकार की ओर से 81 लाख टन गेहूं की खरीद के इंतजाम किए गए हैं।

'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' योजना के अंतर्गत कनक की खरीद 392 मंडियों में की जा रही है। आवक बढ़ी तो मंडियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। सरकारी एजेंसियों ने खरीद के पुख्ता इंतजाम किए हैं तथा फसल मूल्य अदायगी को विशेष व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार व एजेंसियों की ओर से गेहूं व सरसों समेत छह फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। खबर है कि सरसों अपने एमएसपी रेट 4650 रुपए प्रति क्विंटल की बजाय ओपन मार्केट में 5250 से 5500 रुपए तक में बिक रही है।

अनाज मंडियों में जो किसान बिना तय तिथि के कनक लेकर पहुंच रहे हैं, मंडी प्रशासन की ओर से उन्हें भी खरीद सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इसके लिए किसानों को पहले गेट पास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिस कनक में नमी है उसकी खरीद में देर भले हो लेकिन खरीद हो रही है। मंडियों में किसानों के लिए विश्राम करने व सस्ते भोजन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मंडियों में सेनेटाइजर व मास्क उपलब्ध कराए गए हैं। किसानों से आग्रह किया गया है कि वे मंडियों में आवश्यक दिशा निर्देशों की पालना अवश्य करें।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि एक अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले रबी खरीद सीजन 2021-22 के दौरान किसानों को किए जाने वाले भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। किसान को जे-फार्म मिलने के बाद 40 घंटे की अवधि में फसल का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि 72 घंटे में अदायगी नहीं होती है तो सरकार उस राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज देगी। यह भुगतान किसानों के सत्यापित बैंक खातों में सीधे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले सीजन में जिन आढ़तियों को आढ़त व मजदूरी का भुगतान देरी से हुआ है उन्हें देरी से हुए भुगतान पर ब्याज मिलेगा।

### खरीद के लिए पर्याप्त व्यवस्था

रबी फसलों की सुचारू खरीद के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है और संबंधित विभागों और खरीद एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को मंडियों में अपनी उपज बेचते समय किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। फसल के समय पर उठान व खरीद प्रक्रिया के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पहले ही दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं ताकि आढ़ती या किसानों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

### जारी किए गए एसओपी

खरीद प्रक्रिया में शामिल प्रत्येक हितधारक जैसे किसान, आढ़ती, मार्केटिंग बोर्ड, ट्रांसपोर्टर और बैंक आदि के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किए गए है और पूरे खरीद सत्र के दौरान इन एसओपी के कार्यान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, खरीद संचालन में लगे लोगों के स्वास्थ्य जोखिम को कम करने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है।

### शिकायत निवारण सेल

कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि किसानों की खरीद संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए जिला स्तर पर शिकायत निवारण सेल का गठन किया गया है। प्रत्येक जिले में एक उच्च अधिकारी को इन कमेटियों का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यदि किसानों को खरीद प्रक्रिया संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो वे जिला स्तरीय कमेटी में अपनी शिकायत रख सकते हैं । उनकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा।

### आढ़तियों के लिए राहत

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के तहत अनाज मंडियों और सब्जी मंडियों के जो प्लॉटधारक किन्हीं कारणों से समय पर अपनी किस्त का भुगतान नहीं कर पाए, उनके लिए अब हरियाणा सरकार ने डिफाल्ट राशि पर ब्याज में 40 प्रतिशत और दंडात्मक ब्याज को शत-प्रतिशत माफ़ करने का निर्णय लिया है, बशर्ते कि प्लॉटधारक 15 जून, 2021 तक पूरी शेष राशि जमा करवा दें। इस समय हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के 2,421 आबंटी डिफॉल्टर है जिनकी तरफ़ लगभग 1,131 करोड़ की राशि बकाया है। घोषणा के बाद प्लॉटधारकों को 370 करोड़ रुपए (ब्याज में 40 प्रतिशत की छूट और शत-प्रतिशत दंडात्मक ब्याज माफ़ी) का लाभ होगा।

# गुरु तेग़ बहादुर जी का 400वां प्रकाश उत्सव

प्रदेश में गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दौरान विशेष सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। एक मई 2021 को देश और दुनिया भर में भव्य समारोह आयोजित किए जाएंगे, उस दिन हरियाणा सरकार गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी पर तैयार एक कॉफी टेबल बुकलेट जारी करेगी।

इस ऐतिहासिक उत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए कार्यक्रमों की शृंखला शुरू की गई है। नौवें सिख गुरु के सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए हरियाणा सरकार यमुनानगर में मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु तेग़ बहादुर जी के नाम पर रखेगी।

मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल गुरु तेग़ बहादुर जी की 400वीं जयंती को मनाने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गठित उच्च-स्तरीय समिति की बैठक में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा गुरु तेग़ बहादुर जी के साथ एक विशेष बंधन साझा करता है। गुरु जी ने जींद जिले, जिसे उनकी राजधानी के रूप में जाना जाता है, से लोहगढ़ तक की यात्रा की थी। राज्य के युवाओं को गुरु तेग़ बहादुर जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि गुरु तेग़ बहादुर जी के 400वें प्रकाश उत्सव पर जिस यात्रा का आयोजन किया जाएगा, उसमें हरियाणा के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों जो गुरु तेग़ बहादुर जी से संबंधित हैं, को शामिल किया जाए।

संपादकीय

## सावधानी रहेगी तो खेल तमाशा चलता रहेगा

प्रधानमंत्री पूरी गंभीरता के साथ देश की जनता एवं विशेष रूप से युवाओं से आह्वान कर रहे हैं कि वे आगे आएं और कोरोनाकाल की चुनौती को स्वीकार करें। स्वैच्छिक प्रतिबंधों, मास्क, सामाजिक दूरी और स्वच्छता को दैनिक जीवन का अंग बनाया जाए और स्थिति की गंभीरता के दृष्टिगत जीवनशैली में बदलाव लाए जाएं। इस बार प्रधानमंत्री ने 'टैस्टिंग' पर ज्यादा ज़ोर देने का आह्वान किया है जो कि तर्कसंगत भी है और व्यावहारिक भी।

इन दिनों कुम्भ-पर्व चल रहा है। सभी प्रतिबंधों के बावजूद करोड़ों लोग कुंभ-स्नान के लिए हरिद्वार व गंगा-यमुना के अन्य प्रमुख धर्मस्थलों की ओर लपक रहे हैं। अतीत में भी कुंभ और महामारियों की जुगलबंदी चलती रही है। दिल्ली की बाहरी सीमाओं पर किसान आंदोलन, दिशाहीन है, मगर जारी है। वहां भी किसी को चिंता नहीं है।

अतीत में जब तीर्थ यात्री हैजे या प्लेग आदि महामारियों से दम तोड़ देते थे तो उनके सहयात्री उनके शवों को रास्ते में ही सड़ने-गलने के लिए लावारिस छोड़ कर आगे बढ़ जाते थे। अब हालात काफी कुछ बदल तो गए हैं मगर फिर भी कोरोना के मृतकों के शवों के साथ छुआछात का व्यवहार आज भी कायम है।

आर दास गुप्ता (ट्राइम ट्रेंड आफ कॉलेरा इन इंडिया-13 दिसम्बर 2015) के अनुसार हरिद्वार 1891 के कुंभ में हैजे से कुल 1,69,013 यात्री मरे थे। विक्टोरिय पत्नी एवं मार्क हैरिसन (द सोशल हिस्ट्री आफ हेल्थ एंड मेडिसिन पड़ कालोनियल इंडिया) के अनुसार महामारी पर नियंत्रण के लिए नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की सरकार ने मेले पर प्रतिबंध लगा दिया था तथा यात्रियों को मेला क्षेत्र छोड़ने के आदेश दिए जाने के साथ ही रेलवे को हरिद्वार के लिए टिकट जारी न करने को कहा गया था।

सिर्फ हैजा ही नहीं बल्कि चेचक, प्लेग और कालाजार जैसी बीमारियां भी बड़ी संख्या में यात्रियों की मौत का कारण बनती रहीं। सन् 1898 से लेकर 1932 तक हरिद्वार समेत संयुक्त प्रांत में प्लेग से 34,94204 लोग मरे थे। सन् 1867 से लेकर 1873 तक कुंभ क्षेत्र सहित सहारनपुर जिले में चेचक से 20,942 लोगों की मौतें हुईं। सन् 1897 के कुंभ के दौरान अप्रैल माह में प्लेग से कई यात्री मरे।

यह सच है कि ज़िंदगी थम नहीं सकती। ज़िंदगी 'स्टैच्यू' का खेल नहीं है। मगर सावधानी का दामन यथासंभव थामे रहेंगे तो सांसों का खेल-तमाशा भी चलेगा और गहमागहमी बनी रहेगी।

- डा चंद्र त्रिखा

# सफाई कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी

प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। गांव में सफाई का काम करने वाले को साढे 12 हजार रुपए से बढ़कर 14 हजार रुपए तथा शहरी सफाईकर्मी को 15 हजार की बजाए 16 हजार रुपए व सीवरेज मैन को 10 हजार रुपए की बजाए 12 हजार रुपए मासिक वेतन मिलेगा।

वेतन हर माह समय पर मिले इसकी सुनिश्चितता के लिए एक करोड़ की राशि में से सफाई कर्मचारियों के वेतन का भुगतान किया जाएगा। फिर भी यदि किसी कारण से तनख्वाह समय पर नहीं मिलती तो वह अगले महीने 500 रुपए हर्जाना मिलाकर मिलेगी। वित्त विभाग में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए जिस बजट का प्रावधान है, उसे दूसरे किसी कार्य पर खर्च नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने ये घोषणाएं करनाल की कालीदास रंगशाला में आयोजित सफाई मित्र उत्थान सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि सीवरेज की सफाई का काम जोखिम भरा है, इससे सुरक्षा के लिए प्रदेश के रेवाड़ी व गुरुग्राम से एक नई तकनीक का इस्तेमाल शुरू हो गया है। इस व्यवस्था के तहत अब सभी सीवर मेन होल में सेंसर लगाए जाएंगे, ओवर फ्लो होने पर उसका सम्बंधित कार्यालय में अलर्ट आएगा और मशीन से उसकी सफाई सुनिश्चित हो सकेगी।

उन्होंने बताया कि सीवर में काम करते समय व्यक्ति की मृत्यु होने पर सरकार की ओर से दस लाख रुपए बीमा राशि का लाभ दिया जाता है, अब सीवर से अलग डयूटी पर सफाई कर्मचारी की मृत्यु होने पर प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना के तहत पांच लाख रुपए का बीमा लाभ मिलेगा, जबकि सामान्य मृत्यु होने पर दो लाख रुपए की बीमा राशि मिलेगी।

### एक्सग्रेशिया का लाभ मिलेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमानुसार एक्सग्रेशिया (अनुग्रह राशि) का लाभ नियमित कर्मचारी को मिलता है, भविष्य में यह लाभ ऑन रोल पर लिए गए सभी सफाई कर्मचारियों को मिलेगा। एक लाख 80 हजार रुपए सालाना आय वाले सफाई कर्मचारी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बैंकों से बिना किसी गारंटी के ऋण ले सकेंगे, यदि किसी कारण से व्यक्ति ऐसे ऋण की अदायगी करने में असमर्थ हो जाए, तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। सीवर मैन को प्रशिक्षित करेंगे और प्रमाण पत्र हासिल करने वाला ही सीवर की सफाई करेगा। -संवाद ब्यूरो

# फ्लिपकार्ट समूह को 140 एकड़ ज़मीन आवंटित

Flipkart

मानेसर में ई-कॉमर्स कंपनियों से वेयर हाउस बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने फ्लिपकार्ट समूह को हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) की 140 एकड़ जमीन आवंटित की है। जिस पर फ्लिपकार्ट पातली हाजीपुर, मानेसर में 3 मिलियन वर्ग फीट के कवर क्षेत्र के साथ एशिया में आपूर्ति करने के लिए अपने सबसे बड़े आपूर्ति केंद्र को स्थापित करेगा।

हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहरलाल को अवगत कराया गया कि मेससर्स इंस्टाकार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (फ्लिपकार्ट समूह की कंपनी) को यह भूमि 3.22 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की कीमत पर आवंटित की गई है। यह परियोजना क्षेत्र में आगे के निवेश को गति प्रदान करने के साथ-साथ राज्य व उत्तर भारत के वि'ताओं तथा एमएसएमई को बाजार तक पहुंच का अवसर प्रदान करेगी। फ्लिपकार्ट समूह के प्रतिनिधियों ने बताया कि इंस्टाकार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड अपनी मार्केट ग्रोथ को सक्षम करने के लिए पूरे भारत में आपूर्ति केंद्रों और संबंधित लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की एक शृंखला स्थापित करेगा। देश भर में क्षेत्रीय वितरण केंद्र (आरडीसी) का निर्माण करने की योजना बनाई है।

कंपनी की गुरुग्राम के निकट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक लॉजिस्टिक्स कैंपस बनाने की योजना है। उत्तर भारत की मांग को पूरा करने के लिए कंपनी 140 एकड़ क्षेत्र में फैले आपूर्ति केंद्र का निर्माण करेगी। यह आपूर्ति केंद्र अनिवार्य रूप से सामान और फर्नीचर को पार्सल करेगा। इस परियोजना से लगभग 4000 प्रत्यक्ष और 12000 अप्रत्यक्ष रोजगार स्थापित करेगा।


| | |
|---|---|
| सलाहकार संपादक : | डा. चंद्र त्रिखा |
| सह संपादक : | मनोज प्रभाकर |
| संपादकीय टीम : | संगीता शर्मा, सुरेंद्र मलिक, मनोज चौहान |
| संपादन सहायक : | सुरेंद्र बंसल |
| चित्रांकन एवं डिज़ाइन : | गुरप्रीत सिंह |
| डिजिटल सपोर्ट : | विकास डांगी |


# पारदर्शी व्यवस्था के सार्थक परिणाम

परिवहन विभाग में अनियमितताओं को दूर करने के लिए लिए, राज्य सरकार ने 'ऑपरेशन शुद्धि' की शुरुआत की थी, जिसके परिणामस्वरूप नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक पिछले पांच महीनों में 72 करोड़ की राशि वसूल की गई है। नवंबर 2020 से मार्च 2021 तक 25,289 चालान किए गए, जिनमें से 22,431 का निपटान किया गया। 'जन सेवा' की भावना के साथ राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न ई-सुधार किए, जिसमें ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण नीति, खनन की ई-नीलामी, ई-भूमि पोर्टल, अंत्योदय सरल पोर्टल, ई-रजिस्ट्रेशन, सीएलयू की ऑनलाइन मंजूरी शामिल हैं।

### वन टाइम पंजीकरण पोर्टल

ग्रुप 'सी' और 'डी' श्रेणी के पदों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मई, 2021 तक बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने ग्रुप 'सी' और 'डी' श्रेणी के विभिन्न पदों को भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) आयोजित करने की घोषणा की है।

### पीजी छात्रों को पासपोर्ट

विदेश में रोजगार तलाश करने वाले युवाओं के लिए महाविद्यालयों में एक नई महत्त्वाकांक्षी योजना पासपोर्ट सहायता शुरू की गई है, जिसके तहत 6,800 छात्रों को पासपोर्ट दिए गए हैं। अब तक इस योजना में केवल उन छात्रों को पासपोर्ट मिलता था, जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया था। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले सभी स्नातकोत्तर विद्यार्थियों का पासपोर्ट बनाया जाएगा।

हरियाणा में अब हर विभाग में 300 से ऊपर पदों के कादर के लिए ऑनलाइन तबादले होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी विभागों में 'ऑनलाइन तबादला नीति' लागू करने के निर्देश दिए हैं।

हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी कालेजों व विश्वविद्यालयों के परिसरों को तंबाकु-फ्री बनाने का निर्णय लिया है, इसके लिए उच्चतर शिक्षा विभाग ने संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं से किए गए प्रबंधों के बारे में जानकारी मांगी है।

# मॉडल संस्कृति स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम

विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से हर ब्लॉक में मॉडल संस्कृति स्कूल खोले जा रहे हैं। उक्त स्कूलों में सीबीएसई का पाठ्यक्रम लागू किया गया है। गुणवत्तापरक शिक्षा के साथ साथ इन स्कूलों में खेलों को बढ़ावा देने की योजना पर भी काम हो रहा है। राज्य सरकार ने हाल ही में आउटडोर और इनडोर खेल के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए की खेल-कूद की 38 वस्तुओं की भी खरीद के लिए मंजूरी दी है। ऐसे स्कूलों के प्रति बच्चों व अभिभावकों का रुझान बढ़ता जा रहा है।

### प्ले-वे स्कूल होंगे अपग्रेड

बजट अनुमान 2021-22 में शिक्षा के लिए कुल 18,410 करोड़ रुपऽ के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है इसमें से 9,014 करोड़ रुपए प्राथमिक शिक्षा के लिए आवंटित किए गए हैं। लक्षित 4,000 प्ले-वे स्कूल खोलने के प्रस्ताव से बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। पहले चरण में, स्कूल परिसरों या विभागीय भवनों में संचालित 1,135 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले-वे स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा और मार्च, 2021 से परिचालित किये जाएंगे। दूसरे चरण में, 2021-22 में 2,865 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले-वे स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा।

### मॉडल संस्कृति स्कूलों की बढ़ी संख्या

शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल ने बताया कि सीबीएसई के प्रति अभिभावकों के रुझान को देखते हुए ही हरियाणा सरकार ने संस्कृति मॉडल स्कूलों की संख्या 23 से बढ़ाकर 136 की है और ये संस्कृति मॉडल स्कूल सीबीएसई से संबद्ध कराए गए हैं। संस्कृति मॉडल स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है। रेवाड़ी जिला के पांच शिक्षा खण्डों में एक-एक स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल का दर्जा दिया गया है, जिनमें बावल खण्ड के गढ़ी बोलनी, खोल खण्ड के पिथड़वास, नाहड खण्ड के गुडियानी, रेवाड़ी खण्ड के ततारपुर व जाटूसाना खण्ड के बोड़िया कमालपुर का स्कूल शामिल है।

भवनों के निर्माण तक नए सरकारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मौजूदा सरकारी स्कूलों में चलेंगे। इन स्कूलों के लिए शिक्षकों का एक अलग कैडर है और इनका चयन मौजूदा सरकारी स्कूलों के शिक्षण स्टाफ में से स्क्रीनिंग के आधार पर किया जा रहा है।

### मामूली शुल्क

इन स्कूलों में छात्रों से मामूली शुल्क लिया जाएगा। जबकि पहली से पांचवीं कक्षा के छात्रों से 500 रुपए का एक बार प्रवेश शुल्क लिया जाएगा, छठी से 12 वीं तक की कक्षाओं के लिए यह 1,000 रुपए होगा। इसी प्रकार, कक्षा पहली से तीसरी के छात्रों से 200 रुपए, कक्षा चौथी और पांचवीं के लिए 250 रुपए, छठी से आठवीं के लिए 300 रुपए, नौवीं और दसवीं के लिए 400 रुपए और कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए 500 रुपए मासिक शुल्क लिया जाएगा। इन स्कूलों में छात्रों को पर्याप्त परिवहन सुविधा प्रदान की जाएगी।

### क्या होगी सुविधा

कमरों के लिए फर्नीचर, स्मॉक डिटेक्टर, अग्निशमन उपकरण, सीसीटीवी, सौर ऊर्जा पैनल और भूनिर्माण जैसी बुनियादी सुविधाओं के अलावा, ये सभी संस्कृति मॉडल स्कूल छात्रों के लिए डिजिटल सुविधाओं जैसे डिजिटल कक्षा, प्रोजेक्टर, इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड, एलसीडी, डिजिटल पोडियम, क्लाउड आधारित ई-लर्निंग पहल, वाई-फाई और बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से सुसज्जित होंगे। कला और शिल्प स्टूडियो, रोबोटिक्स, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, और जीव विज्ञान की अच्छी तरह से सुसज्जित और आधुनिक प्रयोगशालाओं की व्यवस्था के साथ-साथ लाइब्रेरी या डिजिटल लाइब्रेरी भी इन स्कूलों में बनाई जाएगी।

### प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा

- हरियाणा सरकार का लक्ष्य 2025 से पहले एनईपी के अधिकांश घटकों को लागू करके राष्ट्र के शैक्षणिक मानचित्र पर एक अलग पहचान बनाने का है।
- हरियाणा सरकार ने सक्षम हरियाणा कार्यक्रम के तहत तीसरी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की वैचारिक समझ बढ़ावा देने के लिए 700 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी, जिसमें डिजिटल टैबलेट, डिजिटल क्लासरूम आदि का प्रावधान शामिल होगा।
- समावेशित शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, कक्षा 9वीं से 12वीं तक सभी विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- गुणवत्तापरक शिक्षा और उनके लिए अवसर सुनिश्चित करने हेतु 192 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी। इन समूहों से नामांकन में सुधार हेतु लक्षित समूहों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र (एसईजेड) बनाकर वंचित समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन एसईजेड में छात्राओं को उच्च वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 114.52 करोड़ का एक जेंडर इंक्लूजन फंड (जीआईएफ) बनाया जाएगा।
- आरोही, कस्तूरबा गांधी और मेवात मॉडल स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल के स्तर पर अपग्रेड करके एकीकृत करेंगे।

– संगीता शर्मा

# पलवल से सोनीपत रेल कॉरिडोर से बढ़ेंगे रोज़गार के अवसर

पलवल से सोनीपत तक रेल कॉरिडोर बनाने की योजना पर हस्ताक्षर हुए हैं। हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम, जो हरियाणा सरकार व रेल मंत्रालय का एक संयुक्त उद्यम है ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रौद्योगिकी व आर्थिक सेवाएं प्रदान करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 'राईटस' के साथ इस कॉरिडोर के निर्माण के लिए समझौता किया है।

राज्य में बहु-केंद्रित विकास के माध्यम से लोगों को इको-फ्रेंडली व निर्बाध कनेक्टिविटी मोड की सस्ती एवं सतत परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है।

इससे पूर्व 15 सितंबर, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गठित आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट कमेटी ने 5,617.69 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पलवल से सोनीपत तक हरियाणा ऑरबिटल रेल कॉरिडोर की 121.742 किलोमीटर लंबी दोहरी विद्युतीकृत ब्रॉड गेज लाइन को स्वीकृति प्रदान की थी।

हरियाणा ऑरबिटल रेल कॉरिडोर के निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद राज्य में सार्वजनिक आर्थिक विकास सुदृढ़ होगा और बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की ओर आकर्षित करेगा तथा 'मेड इन इंडिया' मिशन को भी आगे बढ़ाएगा। इस परियोजना से लगभग 76 लाख रोज़गार के अवसर भी सृजित होंगे। इसके अलावा, यह यात्री व माल गाड़ियों में दिल्ली में यातायत भार को कम करेगा।

पलवल से सोनीपत तक का यह कॉरिडोर सोहना, मानेसर तथा खरखौदा तक दोहरी विद्युतीकृत ब्रॉड गेज होगा तथा पृथला डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को भारतीय रेलवे के पलवल, पाटली, सुलतानपुर, आसौदा तथा हरसाना कलां स्टेशनों से निर्बाध कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाएगा। यह परियोजना पांच वर्षों में पूरी होगी तथा इसके लिए एशियन आधारभूत संरचना निवेश बैंक द्वारा फंड उपलब्ध करवाया जाएगा।

-संवाद ब्यूरो

### तीन स्तरीय गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली

पीएमजीएसवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार एक तीन स्तरीय गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का पालन किया जा रहा है। पहले स्तर में समय-समय पर सड़कों का निरीक्षण कार्यपालक अभियंता, उप-मंडल अभियंता और कनिष्ठ अभियंता द्वारा किया जाता है। दूसरे सत्र पर राज्य सरकार द्वारा राज्य गुणवत्ता मॉनिटर नियुक्त किए जाते हैं जो सड़कों का निरीक्षण करते हैं। तीसरे स्तर पर मंत्रालय/ एनआरआरडीए में राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटर नियुक्त किए जाते हैं। पहले और वर्तमान में किए जा रहे सभी कार्यों के लिए सड़कों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। यदि सड़क की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई जाती है या किसी सुधार की आवश्यकता होती है तो प्रदेश सरकार संबंधित पीआईयू/ डिवीजन से एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगवाती है और उनका निवारण करती है।

### 200 किलोमीटर लंबी सड़कों का कार्य पूरा

हरियाणा में यात्रियों की सुविधा के लिए सड़क तंत्र को और मज़बूत करने व यातायात भीड़ को कम करने के लिए हरियाणा सरकार राज्य में 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' (पीएमजीएसवाई) के तहत 688.94 किलोमीटर की कुल लंबाई की 83 सड़कों को अपग्रेड कर रही है, जिस पर कुल 383.58 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। इसमें से 200 किलोमीटर लंबी सड़कों का कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक पूरा हो जाएगा।

### गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर फ्लाईओवर

गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर गांव बधवाड़ी के पास चार लेन का फ्लाईओवर बनने से यह रोड इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा जेवर एयरपोर्ट के बीच सबसे तेज़ रूट होगा। फ्लाईओवर पर लगभग 11.5 करोड़ की लागत आई है। लगभग 514 मीटर लंबाई और 21 मीटर चौड़ाई के इस फ्लाईओवर का निर्माण 21 महीनों में पूरा हुआ।

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने 21 महीनों में इस फ्लाईओवर को तैयार करके फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच मुख्य चैराहे को 'स्टॉप फ्री' बना दिया है।

हरियाणा सरकार ने खरीफ सीजन के दौरान 7.76 लाख मीट्रिक टन बाजरा की खरीद की है। राज्य सरकार 'पारले-जी' कंपनी को बिस्कुट व अन्य खाद्य उत्पाद के निर्माण के लिए बाजरा उपलब्ध करवाने में भरपूर सहयोग करेगी।

आम जनता की सुविधा के लिए, हरियाणा सरकार ने 13 जुलाई, 2020 से बैंकों में ऋणदाताओं द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के ऋण समझौतों के लिए स्टांप शुल्क को 2,000 रुपए से घटाकर 100 रुपए कर दिया है।

# जल संरक्षण से बढ़ा भूमिगत जलस्तर

महेंद्रगढ़ जिले का गांव कौथलखुर्द नारनौल से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। करीब दो हजार आबादी वाले गांव का हर सदस्य जल संरक्षण के प्रति जागरूक है। हर घर नल से जल की आपूर्ति के लिए गांव में भूमिगत टैंक बनाये गए हैं।

कुछ समय पहले तक गांव में स्वच्छ जल का संकट था। महिलाएं दूर टैंक से पानी भरकर लाती थीं। कुछ ही घरों में पानी का कनेक्शन था। 2016 में पढ़ी-लिखी पंचायत बनी तो गांव में परिवर्तन शुरू हो गया। सरपंच सेवानिवृत फौजी परमजीत यादव की मेहनत से काफी काम हुए जिनमें से गांव में स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना और जल संरक्षण करना मुख्य हैं। इससे भूमिगत जलस्तर में निरंतर सुधार की स्थिति भी बनी है।

गांव के 145 घरों में पानी के कनेक्शन होने के बावजूद 115 घरों में जागरूकता के अभाव में टोटियां नहीं थी। जिसकी वजह से गलियों में कीचड़ का आलम रहता था। 2018 में ग्राम पंचायत व जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग द्वारा गांव में जागरूकता अभियान चलाया। जल संरक्षण और उसके सदुपयोग पर बल दिया गया। जिसके बाद आज गांव के हर घर में पानी का वैध कनेक्शन है। निकासी के पानी की उचित व्यवस्था की गई है।

परमजीत ने बताया कि सरकार की योजना के तहत गांव में 1000 से अधिक पौधे लगाए गये हैं। पौधे लगाने का अभियान जारी है। भूमिगत जल रिचार्ज हेतु जोहड़ की खुदाई की गई है। इसमें बरसात का पानी स्टोर किया जाता है।

### जल संरक्षण को बढ़ावा

राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा, द्विवार्षिक जल प्रबंधन योजना बनाने के साथ-साथ गैर-पोटेंबल उपयोग के लिए 25 प्रतिशत उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। फसल विविधिकरण के लिए धान की फसल के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलें उगाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 'मेरा पानी मेरी विरासत योजना' शुरू की गई। इसके तहत किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

सरपंच ने बताया कि गांव का भूमिगत जल स्तर 290 फुट के आसपास था, अब यह 250 फुट के करीब आ गया है।

साल 2018 में गांव को 'जल संरक्षण' पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2020 में महेंद्रगढ़ के उपायुक्त जगदीश शर्मा ने 'मेरा गांव स्वच्छ गांव' के सम्मान से नवाजा। 2018 में गणतंत्र दिवस पर जिला प्रशासन द्वारा स्वच्छता, अवैध कब्जे हटाने और लिंगानुपात बढ़ाने के लिए पंचायत को सम्मानित किया गया।

-संवाद ब्यूरो

# जैविक खेती बनी मुनाफ़े का सौदा

झज्जर जिले के गांव सासरोली के किसान सत्यवान ग्रेवाल सोनीपत कृषि विभाग में सहायक भूमि संरक्षक व मिट्टी परीक्षण अधिकारी हैं। वे ड्रीप प्रणाली के प्रयोग से आर्गेनिक सब्जी उगा अच्छी खासी आमदनी ले रहे हैं। उन्होंने दो एकड़ जमीन में मल्चिंग तकनीक से प्याज लगाया है। प्याज के साथ खरबूजा, भिंडी और मिर्च की भी बिजाई की है। प्याज से पहले कपास लगाई थी। कपास भी ड्रीप प्रणाली से उगाई।

सत्यवान ने बताया कि मल्चिंग के साथ ड्रिप प्रणाली बेहद सरल है। जिससे पानी की बचत तो रहती है साथ खरपतवार नामात्र होने से लेबर पर कम खर्च आता है। मल्चिंग विधि में पूरी तरह आर्गेनिक खाद का इस्तेमाल किया गया है। गोशाला के गोबर को खाद के तौर पर खेत में डाला जाता है। जिसके बाद यूरिया और डीएपी जैसे कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं पड़ती।

उन्होंने बताया मल्चिंग व ड्रिप तकनीक बहुत आसान है। पहले तीन से चार फीट चौड़े मिट्टी के बेड बना लिये जाते हैं। बेड के ऊपर चार से पांच इंच गोबर की खाद बिछा दी जाती है। फिर ड्रीप पाइप लगाने के साथ मल्चींग सीट बिछाई जाती है। इसके बाद पौधा लगाया जाता है। मल्चींग सीट से मिट्टी में नमी बनी रहती है और खरपतवार नहीं होता। जिससे खाद का संपूर्ण फायदा पौधों को मिलेगा।

### खेत से सब्जी की सप्लाई

सब्जियों सीधे उपभोक्ता को सप्लाई करते हैं। दिल्ली और गुरुग्राम के ग्राहक खेत से सब्जी खरीद कर ले जाते हैं। झाड़ली पावर प्लांट के कुछ इंजीनियर एक बार खेत देखने और सब्जी खरीदने आए थे जिन्होंने बाद में वाटसएप ग्रुप बनाया। ग्रुप में 50 से 60 परिवार जुड़े हैं। मैसेज मिलने पर, सब्जी पैकिंग के बाद घरों में सप्लाई की जाती है। वहीं आस-पास के गांव के बहुत सारे परिवार सीधे खेत से सब्जी ले जाते हैं। उन्होंने बताया कि मांग अधिक होने पर सब्जी कम पड़ने लगी, तो अन्य किसान जो आर्गेनिक खेती करने लगे हैं। सत्यवान के पिता धर्मपाल को रोहतक व गज़ौर में राज्यस्तरीय कृषि मेलों में उत्कृष्ट किसान के पुरस्कार से नवाजा जा चुका है।

# वाणिज्य स्तर पर शहद उत्पादन की तैयारी

कुरुक्षेत्र रामनगर स्थित एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र एशिया महाद्वीप का पहला केंद्र है जो मधुमक्खी पालन के लिए भारत एवं इजराइल के सहयोग से वर्ष 2017-18 में बनाया गया था।

केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आधुनिक तकनीकों व संयंत्रों के उपयोग से मधुमक्खी व्यवसाय को वाणिज्य स्तर पर शहद उत्पादन बढ़ाना है। इसके साथ ही स्वस्थ व बीमारी रहित मधुमक्खी कालोनियों के रख-रखाव के लिए प्रबंधन प्रदर्शन लगाना, शहद निकालने, भंडारण, प्रसंस्करण, टेस्टिंग, पैकेजिंग व राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर इसके विपणन को बढ़ाना है।

उद्यान विभाग के महानिदेशक डॉ. अर्जुन सिंह सैनी ने हरियाणा सरकार द्वारा मधुमक्खी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं के बारे में बताया कि इस केंद्र पर स्थापित हनी क्वालिटी कंट्रोल लैब को अपडेट और हनी मंडी स्थापित करने की योजना है। रूझान बढ़ाने व जागरूकता लाने के लिए स्कूली बच्चों का भी इस केंद्र पर भ्रमण कराया जाता है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य सचिव आई.ए.एस. डॉ. सुमिता मिश्रा ने केंद्र पर स्थापित शहद प्रसंस्करण इकाई, छत्ता निर्माण इकाई, वैल्यु एडिशन ऑफ हनी लैब व क्वालिटी कंट्रोल लैब का भ्रमण किया और इस दौरान केंद्र पर अन्य विभिन्न सुधार करने के सुझाव दिये गये। केंद्र पर स्थापित मौन पेटिका निर्माण इकाई में निर्मित उच्च गुणवत्ता के मधुमक्खी के बक्सों को भी देखा।

पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार शून्य उत्सर्जन इलेक्ट्रिक बसें शुरू करना चाहती है। योजना के मुताबिक सकल लागत मॉडल पर राज्य में 124 पूर्णतया इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।

पंचकूला में स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने सेक्टर- 6 स्थित राजकीय वरिष्ठ विद्यालय से की। उन्होंने जिले के 17 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया।

नीली क्रांति

# मछलीपालन बना रोज़गार









संगीता शर्मा

हिसार के सहरवा गांव के संदीप ने वर्ष 2015 में मछलीपालन का काम शुरू किया था। एक हैक्टेयर में झींगा मछलीपालन शुरू किया था, आज सात हैक्टेयर में नवीनतम तकनीक से पर्ल स्पोट, पबदा फिश, मुरेल फिश, सिल्वर पोम्पनो और मिल्क फिश फार्मिंग कर रहे हैं।

संदीप ने भारत सरकार के प्रतिष्ठित संस्थानों से एक्वाकल्चर के कई पहलुओं की जानकारी हासिल करने के लिए प्रशिक्षण लिया। उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडू व गुजरात में जाकर उन स्थलों का दौरा किया जहां पर मछलीपालन अधिक किया जाता है। रिसर्च के बाद यह निकलकर आया कि 70 प्रतिशत सफेद झींगा मछली का पालन किया जा रहा है और अन्य मछली की किस्मों का पालन 30 प्रतिशत है। सफेद झींगा मछली किस्म को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 'वर्ल्ड हैल्दी फूड' की श्रेणी में रखा है।

उन्होंने बताया कि अपनी लंबी यात्रा में उन्हें काफी उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा, लेकिन जुलाई 2019 में गर्व का क्षण आया, जब राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड और राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय, केंद्र सरकार ने 'सेफ एग्रो एक्वा वन सेंटर' की स्वीकृति दी।

उनका कहना है कि मछलीपालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें प्राकृतिक आपदा का कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से मछलीपालन के लिए सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत और महिला एवं अनुसूचित जाति के वर्ग को 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इस अनुदान का उन्होंने फ़ायदा उठाया हुआ।

### आसानी से बिकती हैं मछलियां

संदीप ने बताया कि एक हैक्टेयर में दस मीट्रिक टन तक मत्स्य उत्पादन होता है। सफेद झींगा मछली थोक 300 रुपए किलो की दर से बिकती है। स्वयं दक्षिण भारत के एक्वा फार्म वाले विक्रेता गाड़ी लेकर आते हैं और खरीदकर ले जाते हैं। इसके लिए उन्हें मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने बताया कि मछलीपालन के लिए खारे पानी वाली जमीन की जरूरत होती है और तालाब, ट्यूबवैल, जनरेटर, स्टोर, ऑफिस रूम और मछलियों के फीड आदि की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि पांडुचेरी की गोल्डन मरीन हैचरी से फिश के बीज 60 पैसे की दर से बीज खरीदकर लाते है और एक एकड़ में दो लाख सीड डाला जाता है।

## मत्स्य पालन के लिए सरकार के प्रयास

- मत्स्य पालन को आय और रोजगार सृजन का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। हरियाणा अंतर्देशीय जलीय कृषि के माध्यम से एक प्रमुख मत्स्य उत्पादक है। हरियाणा में औसत 9.6 मीट्रिक टन प्रति हैक्टेयर मत्स्य उत्पादकता दर्ज की गई है, जोकि राष्ट्रीय स्तर पर 3.0 मीट्रिक टन प्रति हैक्टेयर औसत मत्स्य उत्पादकता से अधिक है।
- मत्स्यपालक किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से, हरियाणा सरकार द्वारा 2021-22 से 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत 1090 हैक्टेयर लवणता प्रभावित क्षेत्र और 5,000 हैक्टेयर ताजा पानी वाले अतिरिक्त क्षेत्र का विकास किया जाएगा।
- करनाल और चरखी दादरी में दो बड़े फिश फीड मिल प्लांट स्थापित किए गए हैं। झींगा कल्चर के लिए लवणता प्रभावित क्षेत्र विकसित करने के लिए 2021-22 में भिवानी के गरवा गांव में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।
- 'प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना' के तहत, वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक दस स्माल फिश फीड मिल प्लांट यूनिट स्थापित की जाएंगी। भविष्य में लुप्तप्रायः होने की कगार पर पहुंची मछली प्रजातियों को संरक्षित करने और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए पंचकूला के टिक्कर ताल में 40,000 मत्स्य बीज तथा यमुनानगर, करनाल और पानीपत में पश्चिमी यमुना नहर के प्राकृतिक जल में 16 लाख मत्स्य बीज का स्टॉक किया गया है।

# सौर ऊर्जा आधारित ट्यूबवैल

सौर ऊर्जा आधारित कृषि ट्यूबवैल किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। पानीपत में दर्जनों किसान सौर ऊर्जा ट्यूबवैलों का फ़ायदा ले रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से भी इसे विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है।

बुआना गांव के किसान प्रेम ने बताया की दो वर्ष पूर्व उन्होंने 83 हजार रुपए की लागत से 5 हॉर्स पावर का ट्यूबवैल कनेक्शन लिया था। कम खर्च में उन्हें पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध हो रही है। उन्हें बिजली बिलों से निजात मिली है। उन्होंने बताया कि आवेदन के कुछ समय बाद ही 80% सब्सिडी पर कनेक्शन मिल गया था।

सौर ऊर्जा आधारित कृषि पंप चलाना काफ़ी आसान है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम उपकरण लगे होते हैं। पारम्परिक पंप की तरह बिजली कटौती या कम वोल्टेज आदि की परेशानी नहीं होती है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा लगाये जा रहे इन पंपों के प्रति किसानों का अच्छा खसा रूझान है।

डीजी एनआरई हनीफ कुरैशी के अनुसार प्रदेश में पिछले वर्ष अलग अलग पावर के 15 हजार सौर उर्जा पंप लगवाये थे। इस बार ज्यादा किसान इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक है। इसको लेकर टेंडर हो चुके हैं व इस बार 22 हजार पंप लगाने का लक्ष्य है।

### कैसे करें आवेदन

'किसान अटल सेवा केंद्र' पर जाकर आवेदन कर सकते है। उपभोक्ता अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ता को आधार कार्ड के अलावा जमीन की फर्द लगाना जरूरी है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिन कंपनियों को सरकार अनुमति देती है वे किसान के खेत में जाकर सर्वे करती है व उसके बाद कम से कम पांच या छह महीने में उन्हे पंप का कनैक्शन मिल जाता है। किसान लाभार्थी अगर हिस्सा जमा करवाने के लिए ऋण की सुविधा चाहते है उनके लिए बैंक ऋण की व्यवस्था भी है।

-सुरेंद्र सिंह मलिक

## फसल विविधिकरण से हुआ फायदा

खेती के साथ साथ समाज में बदलाव की मुहिम चलाना अपने आप में उदाहरण है। ऐसी ही एक कहानी है फतेहाबाद के गांव चुहड़पुर के प्रगतिशील किसान हरविंदर की। उन्होंने 1994 में खेती की शुरुआत की थी। स्नातक तक की पढ़ाई करने वाले हरविंदर ने खेती को करियर के तौर पर चुना।

एक एकड़ में आलू तथा एक एकड़ में गन्ना लगाया है जिसमें पूरी तरह से जैविक खाद का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा डेढ़ एकड़ में कपास, डेढ़ एकड़ में मक्का और डेढ़ एकड़ में मूंग की खेती शुरू की है।

### पराली प्रबंधन

उन्होंने पराली प्रबंधन पर काफी कार्य किया है। 25 लाख रुपए लगा कर तीन कृषि यंत्रों की खरीदारी की जिस पर सरकार ने सब्सिडी दी है। 500 एकड़ में हैप्पी सीडर,स्ट्रा चौपर व एसएमएस कंबाईन को लेकर कार्य कर रहे हैं। आसपास के 25 गांव के लोगों ने सोसाइटी बनाकर पराली प्रबंधन पर कार्य शुरू किया है। किसानों के उत्साह को देखते हुए सरकार ने जो कृषि औजार पराली प्रबंधन में सहायक हैं उन पर सब्सिडी 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 80% तक की है।

पराली प्रबंधन से खरपतवार में भारी कमी आती है इससे खेत में सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बड़ा फ़ायदा तब मिलता है जब वो जैविक उत्पाद को मार्केट में लेकर जाते हैं, उनकी फसल आसानी से बिक जाती है।



हरियाणा सरकार ने आढ़तियों के लिए फसल खरीद-सीजन की समाप्ति के 15 दिन के बाद हुई अदायगी पर 9 प्रतिशत ब्याज भी देने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के 9,828 आढ़तियों को लगभग 1.18 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे।



जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में हरियाणा तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस योजना के तहत गांव के प्रत्येक घर को नल से प्रतिदिन 55 लीटर जल उपलब्ध कराना है। प्रदेश में 87 फीसद कार्य पूरा हो चुका है।

# आस्था का प्रतीक माता भीमेश्वरी मंदिर

माता भीमेश्वरी देवी मंदिर झज्जर जिले के बेरी कस्बे में स्थित है। इस मंदिर को बेरी वाली माता के रूप में जाना जाता है। प्रसिद्ध भीमेश्वरी मंदिर में रोज़ाना भक्त आते हैं और देवी की पूजा करते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद, भक्त नारियल और प्रसाद देवी को चढ़ाते हैं। वे अनुष्ठान के एक हिस्से के रूप में मंदिर में देसी घी की 'ज्योति' भी जलाते हैं। नवरात्रि मेले के अवसर के दौरान, नव विवाहित जोड़े मंदिर के पास देवी के सामने गांठ बांधने के लिए जाते हैं। युवा बच्चों के मुंडन समारोह भी यहां किए जाते हैं।

एक लोकप्रिय कहानी के मुताबिक, देवी को भीमेश्वरी नाम दिया गया है क्योंकि देवी की मूर्ति भीमा द्वारा स्थापित की गई थी। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध की शुरुआत से पहले, भगवान श्री कृष्ण ने भीम से अपने कुलदेवी को कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में लाने और उससे आशीर्वाद लेने के लिए कहा। इसलिए, भीमा ने हिंगले पहाड़ के पास गए और अपने कुलदेवी से युद्ध के मैदान में जाने का अनुरोध किया। देवी आसानी से सहमत हो गई लेकिन एक शर्त निर्धारित की। उसने कहा कि वह उसके साथ जाएगी, लेकिन अगर उसने मूर्ति को रास्ते में रखा है तो वह आगे नहीं बढ़ेगी। रास्ते में भीम ने देवी की मूर्ति को एक बेरी पेड़ के नीचे रख दी। भीम को प्यास लगी थी। इसलिए, उन्होंने पानी निकालने के लिए जमीन पर अपने घुटने से टक्कर दी। बाद में, जब उसने देवी की मूर्ति को उठाने की कोशिश की तो अचानक उसे शर्त याद हो आई। भीम ने देवी का आशीर्वाद लिया और कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान कर गए।

बेरी में, दो मंदिर हैं। प्रारंभ में, यह जगह एक घने जंगली थी जिसमें ऋषि दुर्ववास रह रहे थे। हर सुबह ऋषि दुर्वासा बाहरी मंदिर में देवी की मूर्ति लाते और दोपहर में वह मूर्ति को भीतरी मंदिर में रखते। मूर्ति को आंतरिक मंदिर से बाहरी मंदिर तक ले जाने की यह प्रक्रिया अभी भी धार्मिक रूप से पालन की जा रही है। ऋषि दुर्वासा द्वारा गाई गई आरती अभी भी मंदिर में हर दिन गाई जाती है।

धर्मनगरी बेरी में महाभारतकालीन मां भीमेश्वरी देवी मंदिर में कोरोना वायरस के चलते नवरात्रि में इस बार दर्शन करने के लिए पाबंदियां लगाई गई है।

### टोकन सिस्टम से होंगे माता मनसा के दर्शन

चैत्र नवरात्र (13 अप्रैल से 21 अप्रैल)में श्रद्धालु टोकन सिस्टम से ही माता मनसा देवी के दर्शन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, दर्शन की अनुमति सुबह चार से रात 10 बजे तक ही मिलेगी। यह फैसला जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए लिया है। नवरात्र मेले को लेकर जिला सचिवालय सभागार में अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें माता मनसा देवी मंदिर पंचकूला व काली माता मंदिर कालका में होने वाले चैत्र नवरात्र मेले की तैयारियों की समीक्षा की गई।

इमरान रजा ने कहा कि एक घंटे में लिफ्ट से 100 श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था की गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को माता के दर्शन की अनुमति प्रदान की जाएगी। श्री माता मनसा देवी मंदिर पंचकूला में 15 मिनट में 180 के हिसाब से श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे, जबकि काली माता मंदिर कालका में 15 मिनट में 120 श्रद्धालुओं के दर्शन करने की व्यवस्था की जाएगी।

**वेबसाइट पर देवी होगी साधारण जानकारी**

श्राइन बोर्ड की ओर से माता के दर्शन के लिए ई-टोकन की व्यवस्था की गई है। टोकन प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं को केवल बोर्ड की वेबसाइट www.mansadevi.org.in पर साधारण सी जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। इसके बाद उनके मोबाइल नंबर पर एक ई-टोकन भेजा जाएगा, जिसे दिखाकर वे माता के दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा श्रद्धालु फेसबुक पेज जय माता मनसा देवी और यूट्यूब के माध्यम से माता के लाइव दर्शन कर सकेंगे। मेले में माता के दर्शन को छोड़कर भंडारा, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।

# आपसी सहयोग से होगा गांव का समुचित विकास

गांव के समुचित विकास के लिए न तो ग्राम पंचायतें काफी हैं और न सरकार। इसके लिए हर ग्रामीण को जागरुक होना होगा। ग्रामीणों को ग्राम पंचायत, स्थानीय प्रशासन व जन जनप्रतिनिधियों से मिलकर आगे बढ़ना होगा। तभी जाकर गांव को प्रगति के पथ पर ला सकेंगे। 'हमें क्या' या 'तुम कौन' की भावना से उबरना होगा। आने वाली पीढ़ियों के सुखद भविष्य के लिए अहम की भावना को जल्द से जल्द त्यागकर आगे बढ़ना होगा। राज्य सरकार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।

राज्य सरकार ने विकास कार्यों में पारदर्शिता बरतने का संकल्प दोहराते हुए कहा है कि हर ग्रामीण गांव के बारे में न केवल चिंतन करें, बल्कि उस बारे में अपने सुझावों से सरकार को अवगत भी कराए।

कामकाज में ईमानदारी व पारदर्शिता का संकल्प दोहराते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पंचायत स्तर पर होने वाले कार्यों के एक-एक पैसे का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। हर जिले की ऑडिट रिपोर्ट बनाए जाने की योजना है।

गत दिनों पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय में बजट एवं वित्तीय प्रबंधन की योजना के लिए आयोजित बैठक में अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि हर स्तर का बजट निर्धारित फॉर्म पर बनाकर 30 अप्रैल से पहले भेजें ताकि कार्य के लिए समय से बजट जारी हो सके।

उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों को ई पंचायत करने की तैयारी पर कार्य हो रहा है ताकि ई ऑफिस जैसी व्यवस्थाएं शुरू होने से कामकाज में पारदर्शिता आए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अभी 2,713 पंचायतें ऑनलाइन भुगतान कर रही हैं।

**सुझाव आमंत्रित**

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विकास कार्यों को गति देने के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है। विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गांव का कोई भी व्यक्ति अपने गांव के विकास से सम्बंधित सुझाव सरकार को दे सकता है। इसके लिए ग्राम दर्शन पोर्टल पर जाकर अपना सुझाव दर्ज कराएं। पोर्टल पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि यह सुझाव तत्काल पांच लोगों (सांसद, विधायक, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और सरपंच) के पास रिफ्लेक्ट करेगा।

# आओ चलें 48 कोस

प्रदेश में सांस्कृतिक महत्व के स्थलों का कायाकल्प जारी है। साल 2021-22 के बजट में कुरुक्षेत्र 48 कोस भूमि के तीर्थों के विकास में सरकार द्वारा 50 करोड़ आवंटित किये गए हैं। जिसका उद्देश्य 'महाभारत' स्थली को पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 48 कोस में पड़ने वाले कैथल के गांव क्योड़क को गोद लिया है। यहां महाभारतकालीन कोटिकूट नामक तीर्थ है। कैथल से लगभग 11 किलोमीटर दूर यह तीर्थ स्थल 25 एकड़ में फैला है। जिसकी दूर-दराज के गांव में अच्छी-खासी मान्यता है। सरोवर में मृत्यु पश्चात फूल विसर्जित करने की परंपरा है। मान्यता है कि यह भूमि मोक्षदायनी है।

क्योड़क गांव में स्थित इस तीर्थ का उल्लेख महाभारत व वामन पुराण में आता है। वहीं ब्रह्म पुराण में भी इस तीर्थ की महत्ता प्रकट होती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार यह तीर्थ में करोड़ों तीर्थ के बराबर है।

सप्तर्षिकुंड च तथा तीर्थ देव्याः सुजम्भकुम
ईह्मरपद कोटिकूट किन्दान किंजप तथा।

किवदंतियों के अनुसार इस तीर्थ में पांडवों की माता कुन्ती ने स्नान किया था। कुन्ती के आत्मग्लानि से युक्त होने पर एक ऋषि द्वारा इन्हें प्रायश्चित के लिए एक करोड़ तीर्थों में स्नान करने का परामर्श दिया। किन्तु करोड़ तीर्थों पर स्नान करना असंभव था तब कुन्ती के पुत्रों ने इस स्थान पर करोड़ तीर्थों का जल एकत्रित किया और कुन्ती ने सरोवर पर स्नान कर पाप से मुक्ति पाई। ऐसा विश्वास है कि इसमें स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के भी इस तीर्थ पर स्नान करने की बात आती है।

तीर्थ सरोवर के पश्चिमी भाग में टीले के ऊपर एक दो मंजिल लाखौरी ईंटों से बना उत्तर मध्य कालीन भवन है। पूरा गांव प्राचीन टीले पर बसा है। पुरातात्विक खुदाई के दौरान इस स्थान से धूसर चित्रित मृदभाण्ड मिले थे। जिनका सम्बन्ध पुरातत्वविद् महाभारत काल से जोड़ते है। वहीं आद्य-ऐतिहासिक काल से लेकर मध्यकाल तक की संस्कृतियों के अवशेष भी मिले हैं।

कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सचिव, मदनमोहन छाबड़ा ने बताया कि कोटिकूट तीर्थ क्योड़क गांव में स्थित होने के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गोद लिया गांव है। तीर्थ के विकास में अब तक लगभग ढाई करोड़ से अधिक खर्च हुआ है। कोटिकूट की तस्वीर बदल रही है। कैथल जिले के 56 ऐसे तीर्थों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जो 48 कोसी परिक्रमा में आते हैं।

**-मनोज चौहान**

हरियाणा में एचआईवी पाजिटिव और एड्स पीड़ित लोगों को हर महीने 2,250 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एचआईवी पाजिटिव और एड्स से पीड़ित लोगों को पेंशन का चेक देकर शुरुआत की।

'हरियाणा रोड एंड ब्रिज डिवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड' ने हाईवे, एक्सप्रेस-वे समेत प्रदेश की बड़ी सड़कें, ओवरब्रिज, मेडिकल कालेज बनाने के अलावा अब राष्ट्रीय स्तर पर अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर कार्य-योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।

# जल प्रबंधन पर उच्च स्तरीय बैठक

पानी का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है और पानी की हर बूंद को बचाने तथा इसके उचित प्रबंधन के लिए राज्य सरकार ने एक द्विवार्षिक योजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य पानी का उपयोग और उपचारित पानी का पुनः उपयोग सुनिश्चित करना है।

जल प्रबंधन से संबंधित इन सभी कार्यों को एक मिशन मोड पर करने की जरुरत है। प्रत्येक विभाग को इस सिद्धांत से कार्य करने की आवश्यकता है कि लोगों को पीने का पानी प्रदान करना जितना जरूरी है उतना ही पानी का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना भी है। इसलिए, ग्रे-वॉटर मैनेजमेंट को प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री मनोहरलाल व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की

उपस्थिति में शिवधाम नवीनीकरण योजना और ग्रे वाटर मैनेजमेंट की समीक्षा बैठक हुई जिसमें स्वच्छ भारत मिशन में ग्रे-वॉटर प्रबंधन पर विशेष बल देने पर चर्चा हुई। हरियाणा के सभी गांवों में ग्रे-वॉटर प्रबंधन की आवश्यकता है, इसलिए सभी संबंधित अधिकारी और उपायुक्त ग्रे-वॉटर प्रबंधन हेतु परियोजनाएं तैयार कर 30 जून, 2021 तक प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी सभी परियोजनाओं को ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में दर्शाया जाना चाहिए। इसके अलावा, संबंधित विभागों के साथ तालमेल करके ग्राम पंचायतवार परियोजनाएं तैयार की जाएं। परियोजनाएं तैयार करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई बड़ा गांव न छूटे।

कृषि, बागवानी, स्कूल और उद्योग प्रबंधनों के साथ नियमित बैठकें करने के लिए कहा गया है ताकि इन सभी स्थानों पर जहां भी पानी की आवश्यकता है उपचारित पानी का उपयोग हो सके।

### परियोजनाओं में भागीदारी

शिवधाम नवीनीकरण योजना के बारे में उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि परियोजनाओं में लोगों की कम से कम 50 फीसदी भागीदारी के साथ श्मशान घाटों /कब्रिस्तान में किए जाने वाले कार्यों को पूरा करवाएं। उन्होंने उपायुक्तों को शिवधाम नवीनीकरण योजना के तहत कार्यों को पूरा करने के लिए जिला खनिज निधि (खान और भूविज्ञान विभाग) का उपयोग करने की संभावना तलाशने के भी निर्देश दिए।

## आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवाएं

'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए 30 अप्रैल तक पात्र व्यक्ति का गोल्डन कार्ड फ्री में बनाएं जाएंगे। इसके लिए एसईसीसी-2011 की सूचि में शामिल व्यक्ति अपना गोल्डन कार्ड नजदीक अटल सेवा केन्द्र या अस्पताल में बनवा सकता है।

सोनीपत के अतिरिक्त उपायुक्त अशोक बंसल ने कहा कि एसईसीसी-2011 (सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011) की सूचि में शामिल सभी परिवारों को योजना के तहत लाभार्थी माना गया है। इस योजना के तहत लाभार्थी का पहचान पत्र, जिनको 'गोल्डन कार्ड' या 'ई कार्ड' कहा जाता है, जारी किए जा रहे हैं। इसलिए सभी पात्र व्यक्तियों से अपील है कि वे जल्द से जल्द अपना आयुष्मान भारत पहचान पत्र बनवाएं और इस योजना का लाभ उठाएं।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लाभार्थी को पांच लाख सालाना तक का स्वास्थ्य बीमा , जिसमें सभी गंभीर बीमारियों के इलाज शामिल हैं, सभी सरकारी या प्राइवेट सूचीबद्ध अस्पतालों में निशुल्क दिया जाता है। लाभार्थी परिवार चाहे तो पांच लाख तक का खर्च किसी एक सदस्य की बीमारी पर या सभी सदस्यों के इलाज पर मिलाकर कर सकता है।

## अनुलोम-विलोम के पांच फ़ायदे

प्राणायाम अभ्यास सांस लेने की तकनीक पर केंद्रित है और अनुलोम-विलोम उनमें से एक है। यह एक श्वास तकनीक है, जो पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका कोई साइड-इफेक्ट भी नहीं है।

**बेहतर नींद लेने में मदद**

नियमित रूप से अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से रात को अच्छी नींद आती है। सुबह उठते हैं तो तरोताजा महसूस करते हैं। यह पैरासिम्पेथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करने में मदद करता है जिससे शरीर को आराम मिलता है।

**त्वचा में निखार**

यह श्वसन व्यायाम रक्त को शुद्ध करने में मदद करता है। अनुलोम-विलोम से जैसे जैसे ऑक्सीजन अधिक मिलती है, त्वचा में निखार आने लगता है।

**तनाव मुक्त**

अनुलोम-विलोम मूड को शांत करता है, क्रोध कम करने में मदद करता है और कार्य में एकाग्रता बेहतर बनाता है। नियमित रूप से यह क्रिया दोहराते है।

**माइग्रेन से राहत**

माइग्रेन के लिए सबसे प्रभावी योगासन माना गया है अनुलोम-विलोम। हर रोज 15 मिनट करने से माइग्रेन के दर्द में कमी महसूस की जा सकती है।

**मन को शांत**

अनुलोम-विलोम में सांस लेने की तकनीक तनाव को प्रबंधित करने में मदद करती है, मानसिक स्थिरता में सुधार करती है, मन को शांत करती है, चिंता और अवसाद को कम करती है।

योग विशेषज्ञ के मुताबिक अनुलोम-विलोम कई रोगों से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। जैसे अस्थमा, एलर्जी, कब्ज, गैस्ट्रिक एसिड, खर्राटे, हृदय स्वास्थ्य आदि। जरुरत नियमित रूप से यह आसन करने की है।

संवाद ब्यूरो

## कोविड चुनौती से निपटने के प्रयास तेज

स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने बताया कि कोविड-19 की वैक्सीन लगाने के लिए राज्य भर में 1181 टीकाकरण केंद्र संचालित हैं। वैक्सीन की अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इन केंद्रों को रणनीतिक रूप से राज्य भर में अत्यधिक आबादी वाले और यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थापित किया गया है ताकि संक्रमक कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोका जा सके।

अरोड़ा ने कहा कि 1,90,289 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक और लगभग 1,15,038 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविड-19 की दूसरी खुराक मार्च माह तक दी जा चुकी है। इसी प्रकार 1,20,543 फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की पहली खुराक और 43,916 को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जा चुकी है।

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में कोविड अस्पतालों को फिर संचालित किया जा रहा है। कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद राज्य सरकार ने इन अस्पतालों को बंद कर दिया था। कोरोना टीकाकरण में करीब 21 लाख लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है।

राज्य सरकार ने माह के अंत तक 35 लाख टीके लगाने का लक्ष्य रखा है। टीकाकरण में डोज की कमी न बन पाए, इसके लिए गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज स्वयं टीकाकरण अभियान की प्रगति पर नजर रख रहे हैं।

प्रदेश में कोरोना टेस्ट के सेंपल की रिपोर्ट देर से मिलने के कारण कोरोना के नए स्ट्रेन का पता लगाने में देरी हो रही है। अनिल विज ने बताया कि हम प्रदेश में टेस्टिंग की मात्रा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में कोविड-19 की जांच के लिए 35 लैब संचालित हैं, जिनमें करीब 92 हजार टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में आइसोलेशन वार्ड, वेंटीलेटर, सामान्य बेड, आक्सीजन सुविधायुक्त

बेड, आइसीयू, दवाइयां तथा उपकरणों की संख्या पर्याप्त मात्रा में है। उन्होंने केंद्र से अनुरोध किया कि प्रदेश सरकार द्वारा जांच के लिए जो सेंपल भेजे जाते है, उनकी रिपोर्ट शीघ्र भेजी जाए ताकि नए स्ट्रेन का पता लगाकर उसका उपचार किया जा सके।

संवाद ब्यूरो

सेवानिवृत्त आईएएस धनपत सिंह को हरियाणा का नया राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने धनपत सिंह को राज्य चुनाव आयुक्त के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

हरियाणा में 9 वीं से 12 वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क शिक्षा के प्रावधान को लागू करने के लिए 350 करोड़ रुपए सालाना खर्च होने का अनुमान है। यह जानकारी शिक्षा निदेशालय की बैठक में दी गई।

# जनमानस को राह दिखाता लोक साहित्य

मनोज प्रभाकर

हरियाणा कला परिषद द्वारा पानीपत में आयोजित सांग उत्सव में जब 'पिंगला भरतरी' का किस्सा मंचित हो रहा था तो एक बुजूर्ग दर्शक फफक-फफककर रोने लगा। कलाकार उस दौरान गीत गा रहा था- 'भाई रै, इब तेरा लाड करणिये..।' साथ बैठे दर्शकों ने उसकी विडियो बनाई और उसे समझाया बुझाया।

यह हरियाणवी लोक संगीत की ताकत है। भावनाओं को उद्वेलित कर देने वाली इस ताकत की सृजनात्मकता के पीछे महान लोकसाहित्यकारों की जीवन साधना रही है। प्रसिद्ध गीतकार, संगीतकार व कहानीकारों ने अपने अखुट तप से यहां की संस्कृति को समृद्ध करने का काम किया है। यूं कहिए कि प्रदेश के सूफी लोकगायकों, जिन्हें सांगी भी कहा जाता है, ने राष्ट्र को ऐसा अनमोल तोहफा दिया है जिससे हमारी लोकसंस्कृति देदीप्यमान हो रही है। इसी कालजयी लोकसाहित्य की वजह से समाज में समय-समय पर आई विसंगतियां तिरोहित हुई हैं।







हिंदी के अलावा स्थानीय बोली से संबद्ध साहित्य मनीषियों ने लोक को ऐसा प्रकाश दिया है जिससे संस्कृति सदैव आलोकित होती रहेगी। कहते हैं जो राष्ट्र अपनी परंपराएं व संस्कृति को नहीं भूलता वह कभी पराजित नहीं हो सकता। इन परंपराओं के संवाहकों में हरियाणा के सूर्य कवि दादा लख्मीचंद का नाम सर्वोपरि आता है। ऐसे महान विद्वानों की फेहरिस्त लंबी है।

लोकसाहित्य की भाषा स्थानीय होती है और स्थानीय भाषा में अभिव्यक्ति व्यापक होती है। इतनी व्यापक कि उसमें भावों की प्रधानता रहती है जो आत्मीयता के समीप ले जाते हैं। हरियाणा प्रदेश के लोग जब विदेशों में मिलते जुलते हैं तो कुछ देर की बातचीत के बाद सीधे 'अपनी बोली' पर आ जाते हैं। यूं कहिये कि वे अपनी बोली पर नहीं आते, बल्कि उनकी अपनी संस्कृति उनके फासलें समाप्त कर देती है। जो बोली नाभिक्षेत्र से निकलती है उसमें अपनत्व होता है। अपनेपन के प्रकाश से सभी भेद रूपी अंधकार समाप्त होने लगते हैं।

लोकसंस्कृति के रंगों से सराबोर गीत- संगीत, रागनी, आल्हा, नृत्य व बीन के लहरे हमारे जीवन में रंग भरने का कार्य करते हैं। जरुरत है इन विद्याओं को जीवंत रखने की, और यह कार्य वर्तमान सरकार के मार्गदर्शन में हरियाणा कला परिषद बखूबी कर रहा है। परिषद से जुड़े सैंकड़ों कलाकार सांग व इन्डोर नाटकों का मंचन कर रहे हैं। कला परिषद के अतिरिक्त निदेशक महाबीर गुड्डू ने बताया कि अपने लोक साहित्य की अनेक विद्याएं आज भी प्रासंगिक हैं। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने इस क्षेत्र को जो तवज्जो दी है वह हम सभी के लिए गौरव की बात है। गीत-संगीत भगवान का एक प्रतिस्वरूप है जिसके संपर्क में आने से हर प्राणी को सुकून मिलता है।

गायक रमेश कलावड़ ने दादा लख्मी की एक रागनी के जरिए बताया कि हर चीज और रिश्ता अपनी जगह अच्छा लगता है। बिना मेल का कोई सौदा नहीं होता। जैसे-

**चोरी का धन ओस का पानी, के बादल की छाया।**
**के वेश्या की प्रीत जगत में, के सपने की माया।**
**के साली का याराना, साद्दू रिश्तेदार किसा**
**के रंडवे का घरवासा, दुश्मन पै एतबार किसा**
**जो ऊंच नीच न जाणै कोन्या, कृपण साहूकार किसा**
**घरां बीर की गैल्यां आया, दादा का हक्दार किसा।**

## बलि और शंभू ने दिया जीने का संदेश

लगभग दो घण्टे की अवधि वाले नाटक बलि और शम्भू में वृद्धाश्रम में रहने वाले दो बुजुर्गों की हालत पर प्रकाश डाला गया। नाटक में दिखाया कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो मां बाप से उनकी अपेक्षाएं भी बड़ी होने लगती हैं। फिर बड़े होने के बाद बच्चे अपने मां बाप से दूर चले जाते हैं। कुछ रह जाता है तो बस अपेक्षाएं। प्यारी नोकझोक के बीच कलाकारों ने जिंदगी की सच्चाई और बुढापे की पीड़ा को बयां किया तो दर्शक भावुक हो गए।

नाटक बलि और शम्भू ने ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्गों की भावनाओं को बड़े ही मार्मिक तरीके से पेश कर समाज को आइना दिखाया। नाटक में कलाकारों ने इंसान के अंर्तद्वंद्व को दिखाने का प्रयास किया। एक ओर जहां इंसान जिंदगी के अंतिम पड़ाव में अतीत के पलों ढोते ढोते आखिरी पलों के इंतजार में जिंदगी गुजारने लगता है, वहीं दूसरी ओर इंसान आखरी समय में नये रिश्ते बनाकर जिंदगी को खूबसूरती से जी सकता है।

'पंचलाईट' का अशिक्षा पर प्रहार

## फणीश्वर नाथ रेणू की बहुचर्चित कहानी

जिंदगी में हंसना बेहद जरुरी है। बिना हास्य के जीवन नीरस हो जाता है। एक ओर जहां हास्य तनाव को दूर करता है, वहीं लोगों के अंदर स्फूर्ति भी पैदा करता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला कला कीर्ति भवन की भरतमुनि रंगशाला में। मौका था न्यू उत्थान थियेटर ग्रुप द्वारा मंचित हास्य नाटक पंचलाईट का। हरियाणा कला परिषद द्वारा विश्व रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सात दिवसीय नाट्य रंग महोत्सव के समापन पर कुरुक्षेत्र के रंगकर्मी विकास शर्मा के निर्देशन में फणीश्वर नाथ रेणू की बहुचर्चित कहानी पंचलाईट को बहुत ही रोचक ढंग से मंचित किया गया।

शहर के एकमात्र सक्रिय नाट्य दल न्यू उत्थान थियेटर ग्रुप द्वारा विकास शर्मा के निर्देशन में प्रस्तुत नाटक पंचलाईट में बिहार के एक छोटे से गांव की कहानी को दिखाया गया। उस समय गांव में बिजली नहीं होती थी। गांव के बामन टोली के पास खुद की खरीदी हुई पंचलाईट थी, तो महतो टोली के लोगों ने भी दण्ड और जुर्माने के पैसे इक्ट्ठे करके पंचलाईट खरीद ली। जब शहर से पंचलाईट गांव में आती है तो खूब खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि गांव के किसी भी व्यक्ति को पंचलाईट जलानी नहीं आती। लेकिन गांव का एक आवारा लड़का गोधन जो पढ़ा-लिखा है, उसे ही पंचलाईट जलानी आती है। गोधन गांव की ही लड़की मुनरी से प्यार करता है। लेकिन मुनरी से प्यार करने वाले कल्लू को ये अच्छा नहीं लगता और वह मुनरी की अम्मा को सब बता देता है। मुनरी की अम्मा पंचायत बुला लेती है, जिसमें फैसला होता है कि गोधन का पानी बंद कर दिया जाए। इस प्रकार गोधन और मुनरी का मिलना-जुलना बंद हो जाता है। लेकिन पंचलाईट आने पर मुनरी सबको बताती है कि गोधन को पंचलाईट जलानी आती है।

सरपंच गोधन को बुलवाकर पंचलाईट जलाने के लिए कहता है, लेकिन गोधन शर्त रखता है कि यदि मुनरी से उसका ब्याह करवाया जाए, तभी वह पंचलाईट जलाएगा। पंचायत उसकी बात मान लेती है और गोधन का मुनरी से ब्याह करवाने का वादा करती है। तब गोधन पंचलाईट जला देता है और पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। इस प्रकार नाटक अशिक्षा पर कटाक्ष करता है।

## माया का सै खेल जगत मं, माया सबनै प्यारी

माया का सै खेल जगत मं, माया सबनै प्यारी
इस माया नै पागल कर दी, सारी दुनियादारी।
माया खातिर हवन यज्ञ हों, माया खातिर पुण्य दान
जिसके धोरै माया कोन्या, लागै मूर्ख वो इंसान।
माया बिन सुख जग मं, बिन माया यू किसा जहान
माया बिन खुद भाइयां मं, होता कोन्या आदर मान ।
सब तरियां परेशान रह सै, माया बिन घर- बारी
इस माया नै पागल कर दी, सारी दुनियादारी।
माया बिन ना कोई प्यारा, माया बिन ना भाता
माया बिन टूटता दिखै, पिता पुत्र का नाता।
सारे लोग कहैं सैं पागल, बोल्या भी ना जाता
माया बिन छोड़कै चलदे, गत फेरां की ब्याहता।
सत्य किसे कै सूझ ना पाता, जिब लेज्या हंस उडारी
इस माया नै पागल कर दी, सारी दुनियादारी।
माया बिन कोए कितै भी, आवै -जावै कोन्या
जीणा मुश्किल होज्या, रस्ता पावै कोन्या।
माया हो बस माया, घणा ज्ञान सुहावै कोन्या।
माया बिन यू जगन्नाथ भी, हरगिज गावै कोन्या।
भागां बिन न्यू आवै कोन्या,
चाहे लाख करो होशियारी
इस माया नै पागल कर दी सारी
दुनियादारी। ।

-गायक प्रीती चौधरी

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com